राज्य पुलिस उपाधीक्षक

बनाम

बी.टी. रमेश और अन्य।

(सिविल अपील संख्या (9463-9465 / 2025)

14 जुलाई 2025

[दीपांकर दत्ता*, न्यायाधीश

और

मनमोहन, न्यायाधीश]

विचारणीय मुद्दा

यह मुद्दा उठा कि क्या उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में न्यायोचित था, इस आधार पर कि कथित घटना की तारीख के चार साल से अधिक समय बाद आरोप पत्र दायर किया गया था और अनुशास्ति की कमी थी; और क्या कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 214 में भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या किसी समान कानून के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को दबाने के लिए कोई उपयोजन है।

शीर्ष टिप्पणीयां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 197, 482 - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 - नियम 214 - आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना - अभियोजन की अनुमोदन - भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही को दबाने के लिए नियम 214 का आवेदन - सरकारी विभाग में प्रतिवादी-मुख्य अभियंता ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ - भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज - आरोप पत्र दाखिल करना - उच्च अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आरोपपत्र कथित घटना की तारीख के चार साल से अधिक समय बाद दायर किया गया था और अनुमोदन की कमी थी - यथार्थता :

अभिनिर्धारित: नियम 214, निर्माण के किसी भी नियम द्वारा, प्रारंभिक चरण में लंबित आपराधिक कार्यवाही को दबाने के लिए या अपराध का संज्ञान लेने के बाद ऐसी कार्यवाही को दबाने के लिए कोई आवेदन नहीं है, इससे बेहतर कोई कारण नहीं है कि उसमें निहित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया है - उच्च न्यायालय ने नियम 214 का हवाला देते हुए प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो, कोई उपयोजन नहीं था - इस आधार पर कि कार्यवाही को रद्द करने के लिए कथित घटना की तारीख के चार साल से अधिक समय बाद आरोप पत्र दायर किया गया था, असंपोषणीय- जहां तक धारा 197 के तहत अनुमोदन का संबंध है, उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की कार्यवाही को रद्द करने में गलती की क्योंकि यह इस बात की मूल्यांकन नहीं करता था कि 2018 में संशोधन से पहले इसकी धारा 19 केवल उन लोक सेवकों पर लागू होती थी जो अपराध का संज्ञान लेने के समय पद पर थे - इस प्रकार, चूंकि प्रतिवादी 2012 में सेवानिवृत्त हो गया था और अपराध का संज्ञान लिया गया था, अपनी सेवानिवृत्ति के चार साल बाद, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत संरक्षण के हकदार नहीं थे - इस तरह की सुरक्षा उन्हें केवल तभी उपलब्ध होती जब उनके सेवा में रहते हुए संज्ञान लिया जाता - उच्च न्यायालय ने पहले आधार पर कार्यवाही को रद्द करने में गलती की कि कथित घटना की तारीख के चार साल से अधिक समय बाद आरोपपत्र दायर किया गया था, पूरी तरह से; और अनुमोदन की कमी के दूसरे आधार पर, आंशिक रूप से - आक्षेपित आदेश, धारा 13(1)(सी) और (डी) धारा 13(2) के साथ पढ़े - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कार्यवाही को रद्द करना - प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही बहाल की गई और ऐसे अपराधों के लिए जारी रह सकती है। अनुच्छेद 16-25]

कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 - नियम 214 - कदाचार या लापरवाही के लिए पेंशन रोकना या वापस लेना - नियम 214 का दायरा - स्पष्टीकरण किया गया। [अनुच्छेद 16-17]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

पंजाब राज्य बनाम कैलाश नाथ **[1988] पूरक 3 एससीआर 911: (1989)1 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 321;** *ए श्रीनिवासुलु बनाम तमिलनाडु राज्य।* **[2023] 10 एससीआर 11 :(2023) 13 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 705 - संदर्भित किया गया है।**

मोहम्मद हनीफ बनाम तीर्थहल्ली पुलिस, **1985 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 203;** *ए.के. चौडेकर बनाम कर्नाटक राज्य,* **2013 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 10754;** *कर्नाटक राज्य बनाम पी. गिरिधर कुडवा,* **2020 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 5723 - संदर्भित किया गया है।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958; भारत का संविधान; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; कर्नाटक सिविल सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1985

प्रमुख शब्दों की सूची

रद्द करना ; आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना; लोक सेवक; आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया; अनुमोदन ; अभियोजन की अनुमोदन आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन; सेवानिवृत्त लोक सेवक; अनुमोदन की कमी; आपराधिक कार्यवाही को दबाना; संविधि की निर्वचन; गठन का नियम; आरोप पत्र; सरकारी राजकोष को हानि; संज्ञान।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9463-9465 /2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु ने रिट याचिका संख्या 61305, 61306 और 61307/ 2016 मे दिनांक 05.07.2022 को निर्णय और आदेश दिया।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता:

देवदत्त कामत, वारिष्ट अधिवतका, डी. एल. चिदानंद, अजय देसाई, रेवंत सोलंकी।

प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता :

इस अवसर पर श्री गोपाल शंकरनारायणन, आनंद संजय एम नूली, वरिष्ठ अधिवक्ता मृगांक प्रभाकर, सुश्री इशिता चौधरी, शौर्या दासगुप्ता, सुश्री अदिति गुप्ता, सिद्धार्थ साहू, सूरज कौशिक, अदिति गुप्तामैसर्स , नुली और नुली उपस्थित थे।**सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

<u>निर्णय</u>

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता,

1. अनुमति दी गई।
2. कर्नाटक राज्य की वर्तमान अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय[2] के 5 जुलाई, 2022[1] के सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं, प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं[3] में - बीटी रमेश[4] संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973[5] की धारा 482 आक्षेपित आदेश के माध्यम से, तीन रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप रमेश के खिलाफ तीन परिवाद मामलों[6] में कार्यवाही रद्द कर दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष तीन अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर करने का अवसर तब आया जब रमेश के खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक कार्यवाही (विशेष आपराधिक मामला संख्या 252, 273 और 253/2016) लंबित थीं। इस तरह की सभी कार्यवाही में, 3 जून 2016 को एक सामान्य आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें रमेश को कई आरोपियों में से एक के रूप में पेश किया गया था।

4. वर्तमान अपीलों के निपटान के लिए संक्षेप में आवश्यक तथ्य ये हैं।

---

1. आक्षेपित आदेश
2. उच्च न्यायालय
3. रिट याचिका संख्या 61305/2016 (जीएम-आरईएस) शिकायत निवारण रिट याचिका संख्या 61306 / 2016 शिकायत निवारण रिट याचिका संख्या 61307/2016
4. रमेश
5. आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण
6. विशेष सीसी संख्या 252/2016, 253/2016 और 273/2016

(अ) 15 फरवरी, 2008 से 15 जनवरी, 2011 तक रमेश मुख्य अभियंता, बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका[7] (पश्चिम) के रूप में कार्य कर रहे थे और उनके पास 30 लाख से 60 लाख के बीच अनुमानित कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति थी।

(आ) 26 मार्च, 2009 को रमेश ने कतिपय मुख्य सड़कों और चौराहों के निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी।

(इ) 3 नवंबर, 2011 को, दूसरे प्रतिवादी[8] ने बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका के कार्यालय द्वारा कार्यों के निष्पादन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोपी के रूप में किसी का नाम नहीं था।

(ई) अगले दिन, 4 नवम्बर, 2011 को भारतीय दंड संहिता, 1860[9] की धारा 420, 406, 409, 465, 468, 471, 477(क) और 120 ख और कर्णाटक स्पष्टता सार्वजनिक खरीद अधिनियम, 1999 की धारा 23 के अंतर्गत उक्त परिवादी वाद संख्या 4/2011 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(उ) 31 मई, 2013 को, रमेश सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

(ऊ) इस तरह की सेवानिवृत्ति के तीन साल से अधिक समय के बाद और शिकायत दर्ज होने के लगभग चार साल और सात महीने बाद, अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने 3 जून, 2016 को अपराध संख्या 4/2011 (विशेष आपराधिक मामला संख्या 252/2016) में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें रमेश को धारा 120 (बी), 409 के तहत आरोपी संख्या 6 के रूप में शामिल किया गया

(ऋ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988[10] की धारा 13(1)(ग) और (घ) और 13(2) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 468, 477 के अंतर्गत धारा 13(1)(ग) और (घ) और 13(2) के संबंध में धारा 10 के तहत धारा 465, 468, 477 के मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपपत्र के अनुसार, रमेश पर संबंधित समय

---

7. बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका
8. आयुक्त, बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका, एनआर स्क्वायर, बैंगलोर
9. भारतीय दंड संहिता
10. आयुक्त, बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका, एनआर स्क्वायर, बैंगलोर

पर बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका के मुख्य अभियंता के रूप में सेवारत रहने के दौरान सह-आरोपी (बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका के अन्य अधिकारी और ठेकेदार) के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने निर्माण वस्तुओं के लिए निर्धारित लोक निर्माण विभाग दरों की अनुसूची दरों के बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग अनुसूची दरों को अपनाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप 22 लाख 40 हजार रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि का दुरुपयोग हुआ, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

(ए) विशेष सीसी संख्या 252, 273 और 253/2016 में कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए, रमेश ने उच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं प्रस्तुत कीं, जिन पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष रमेश ने तीन दलीलें दीं:

(i) 2009-2010 में कथित रूप से हुए अपराधों के लिए, आरोप पत्र कथित घटना के सात साल से अधिक समय बाद 3 जून, 2016 को दायर किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह देरी कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958[11] के नियम 214 (3) के तहत कार्यवाही को प्रतिबंधित कर देती है, जो न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए चार साल की सीमा अवधि निर्धारित करती है, जिसकी गणना उस तारीख से की जाती है जिस दिन कथित कदाचार या अपराध हुआ था; (ii) कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958[11] के नियम 214 (6) (बी) के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही के संबंध में "न्यायिक कार्यवाही", मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की तारीख से शुरू माना जाएगा और प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख अप्रासंगिक है; और (iii) धारा 197, आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण के तहत रमेश के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं की गई थी।

6. उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए, राज्य ने प्रस्तुत किया: (i) कार्यवाही कथित घटना की तारीख से दो साल के भीतर शुरू की गई थी क्योंकि प्राथमिकी 2011 में दर्ज की गई थी; और (ii) चूंकि आरोप पत्र रमेश की सेवानिवृत्ति के बाद दायर किया गया था, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

7. रमेश की दलीलों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द कर दिया। अन्य *बातों के साथ-साथ* यह माना गया कि:

---

11. कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958

"8. निर्णयों के नियम 214 (3) और उप-नियम (6) (बी) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान स्थापित नहीं की गई है, चाहे वह उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुन: नियोजन के दौरान उत्पन्न हुई कार्रवाई के कारण के संबंध में या ऐसी संस्था से चार वर्ष से अधिक समय पहले हुई किसी घटना के संबंध में स्थापित नहीं की जाएगी।

9. वर्तमान मामले में, दुर्विनियोग का कथित अपराध वर्ष 2009-2010 के दौरान हुआ है। हालांकि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वर्ष 2011 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन कार्रवाई के कारण की तारीख से चार साल की समाप्ति के बाद 03.06.2016 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान निर्णयों के नियम 214(3) और उप-नियम-6 के विपरीत है और इसे कानून के अधिकार के बिना माना जाता है।

10. आरोप पत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए भी दायर किया गया है, हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ता-आरोपी संख्या 6 पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आरोप पत्र दायर करने की तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। धारा 197(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान नहीं लेगा जो न्यायाधीश या लोक सेवक के रूप में न्यायाधीश है या था, जिसे पूर्व स्वीकृति के बिना अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए, भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत करने से पहले पुलिस को आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण की धारा 197 (1) के तहत निर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता थी और आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण की धारा 197 (1) के तहत निर्दिष्ट अनुमोदन के अभाव में, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान इस हद तक कि यह भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है, कानून के अधिकार के बिना माना जाता है।

11 पूर्ववर्ती विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता-आरोपी संख्या 6 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और तदनुसार, मैं निम्नलिखित पारित करता हूं:

आदेश

i. रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

ii. रिट याचिका संख्या 61305/2016 में विशेष आपराधिक वाद संख्या 252/2016,विशेष आपराधिक वाद संख्या 273/2016 और विशेष आपराधिक वाद संख्या 253/2016 में आक्षेपित कार्यवाही हुई और 77वें शहर के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश द्वारा जहां तक यह आरोपी संख्या 6 से संबंधित है बेंगलुरु की फाइल पर लंबित क्रमशः 61306/2016 और 61307/2016 को रद्द किया जाता है,

8. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत ने निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की:

क आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण की धारा 197 के तहत अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में याचिका आमतौर पर संज्ञान लेने के चरण में निचली अदालत के समक्ष उठाई जानी है;

ख कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 का नियम 214 (3) सेवानिवृत्त लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगाता है। इस तर्क के समर्थन में, उच्च न्यायालय के दो निर्णयों का संदर्भ दिया गया था।

i सबसे पहले, ***मोहम्मद हनीफ बनाम तीर्थहल्ली पुलिस***[12] में, उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सिविल सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 के नियम 214 के परंतुक (सी) की व्याख्या करते हुए [जो कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 214 (3) के अनुरूप है] ने माना कि:

> "**13.** नियम 213 और 214 में निहित प्रावधानों की बारीकी से जांच करने से पता चलेगा कि नियम 213 इस अवधारणा पर आधारित है कि भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन के प्रत्येक अनुदान की एक निहित शर्त होगी और पेंशन के

---

12. 1985 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 203

भुगतान का सम्मान करने वाले पेंशनभोगी के खिलाफ उचित पेंशनभोगी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है, यदि पेंशनभोगी को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या इस अवधि के दौरान गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है। पेंशनभोगी को गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने या गंभीर कदाचार का दोषी पाए जाने के लिए किसी भी अवधि के बिना पेंशन मिलती है; जबकि नियम 214 को लागू किया जा सकता है और पेंशनभोगी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुन:रोजगार पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है, जो विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन है। दूसरे शब्दों में, पेंशनभोगी के भविष्य के कृत्यों और आचरण का सम्मान करते हुए नियम 213 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक गंभीर अपराध की सजा हो सकती है या उसकी सेवानिवृत्ति के बाद गंभीर कदाचार का दोषी ठहराया जा सकता है; जबकि <u>नियम 214 पेंशनभोगी के कार्यों और आचरण के संबंध में लागू होता है, जब वह सेवा में था, जिसके परिणामस्वरूप विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में यह निष्कर्ष निकलता है कि वह गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी है।</u>यही कारण है कि पेंशनभोगी के कृत्यों और आचरण के संबंध में सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अपराध की सजा होती है या गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है क्योंकि वे पेंशनभोगी के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भविष्य के कृत्यों और आचरण से संबंधित हैं और नियम 214 के तहत विभागीय और न्यायिक कार्यवाही के संबंध में सीमा की अवधि निर्धारित की गई है क्योंकि यह पिछले कृत्यों और आचरण पर लागू होता है। पेंशनभोगी, जब वह सेवा में था। दोनों खंड(ख) और (ग) के साथ-साथ नियम 214 के परंतुक में पूर्व या किसी घटना या कार्रवाई के कारण के मामले में किसी भी घटना के संबंध में विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए चार वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, यदि अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति से पहले सेवा में था, तो ऐसी कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही स्थापित नहीं

की गई थी या अपने पुन:रोजगार के दौरान। परिसीमा की यह अवधि ऐसे मामले पर लागू नहीं होती है जहां किसी कर्मचारी के संबंध में विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई थी, जबकि वह सेवा में था। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नियम 214 के परंतुक का खंड (सी) केवल नियम 214 में निर्दिष्ट न्यायिक कार्यवाही को नियंत्रित करता है। यह 'ऐसी न्यायिक कार्यवाही' शब्दों से स्पष्ट है इसका अर्थ है कि नियम 214 में संदर्भित न्यायिक कार्यवाही और सामान्य आपराधिक कानून से निपटने वाले किसी भी आपराधिक न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही सहित अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं। कार्रवाई के कारण के संबंध में न्यायिक कार्यवाही की संस्था के खिलाफ निषेध जो उत्पन्न हुआ या ऐसी संस्था से 4 साल से अधिक समय पहले हुई घटना के संबंध में खंड (सी) में निहित है या किसी भी घटना के संबंध में विभागीय जांच की संस्था के खिलाफ जो ऐसी संस्था से 4 साल से अधिक समय पहले हुई थी, जैसा कि परंतुक के खंड (बी) के तहत निर्धारित किया गया है, केवल नियम 214 के तहत शक्तियां और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। परंतुक के खंड (बी) और (सी) में प्रदान की गई सीमा की अवधि का उद्देश्य उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रतीत होता है, जो अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसी संस्था से 4 साल से अधिक समय पहले उत्पन्न हुई किसी जीर्ण या दूरस्थ घटना या कार्रवाई के कारण के संबंध में विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू करके मुझे ऐसा लगता है कि श्री देसाई द्वारा खंड (सी) में जिन निषेधात्मक शब्दों पर भरोसा किया गया है, उन्हें सामान्य रूप से आपराधिक मुकदमों के खिलाफ एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

(अपीलकर्ता द्वारा अवधारण दिया गया)

उच्च न्यायालय ने माना कि नियम 214 के तहत यह परिसीमा केवल नियम 214 के तहत कार्यवाही पर लागू होती है, न कि सामान्य आपराधिक मुकदमों पर, जो इस नियम से प्रभावित हुए बिना नियमित आपराधिक कानून के तहत आगे बढ़ सकती है।दूसरे, ***एके चौडेकर बनाम कर्नाटक राज्य***[13] में, उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 214(3) से निपटते हुए कहा कि:

---

13. 2013 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 10754

"**9.** नियम 214 के उप-नियम (3) में दिखाई देने वाले 'न्यायिक कार्यवाही' शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। राज्य की मंशा यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद या उसके पुन:नियोजन के दौरान कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती कार्रवाई के किसी कारण के संबंध में जो उत्पन्न हुई या ऐसी संस्था से चार वर्ष से अधिक समय तक हुई किसी घटना के संबंध में, वह सिविल कार्यवाही के संबंध में है, न कि 'आपराधिक कार्यवाहियों' के संबंध में। इस प्रकार, हम मानते हैं कि कर्नाटक सरकारी कर्मचारी सेवा नियम के नियम 214 का उप-नियम (3) एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोकता है, जिस पर दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध करने का आरोप है।

10. यह उल्लेख करना उचित है कि <u>दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध करने वाले सरकारी कर्मचारी को दोषमुक्त करना राज्य का इरादा नहीं हो सकता है</u>।

(अपीलकर्ता द्वारा अवधारण दिया गया)

ग. संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम आपराधिक अभियोजन पर रोक नहीं लगा सकते। उसी के समर्थन में, ***पंजाब राज्य बनाम कैलाश नाथ***[14] पर भरोसा किया गया था:

"7. सामान्य तौर पर जो 'सेवा की शर्तें' शब्द के दायरे में आती है, उसे वेतन या मजदूरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता, आवधिक वेतनवृद्धि, वेतनमान, अवकाश, भविष्य निधि, उपदान, पुष्टिकरण, पदोन्नति, वरिष्ठता, कार्यकाल या सेवा की समाप्ति, अनिवार्य या समय से पहले सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव, प्रतिनियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है। <u>किसी सरकारी कर्मचारी</u>

---

14. (1989) 1 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 321

पर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, इसे स्पष्ट रूप से सेवा की शर्तों से संबंधित नहीं माना जा सकता है। यह प्रावधान करना कि कोई सरकारी कर्मचारी, भले ही वह गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी हो, जो दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या एक समान कानून के तहत दंडनीय अपराध का गठन करता है, को किसी विशेष अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसे अभियोजन से छूट प्रदान की जानी चाहिए ताकि प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके क्योंकि कुशल कार्य न केवल सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा, बल्कि प्रतिकूल भी होगा। यह कुशल कार्य के लिए नहीं बल्कि उनके सेवा के कार्यकाल के अंतिम चरण में उनमें से कुछ कदाचार और लापरवाही सहित अपराध करने के लिए एक प्रोत्साहन होने की संभावना है और यह प्रयास करना कि अभियोजन शुरू करने या अभियोजन शुरू करने के मामले में देरी करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपराध का पता न लगाया जाए। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण नहीं हैं जहां कोई सरकारी कर्मचारी साक्ष्य के अभाव में प्रारंभिक चरण में अभियोजन से बच सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के अभियोजन के दौरान साक्ष्य पेश किया जा सकता है या ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है जो ऐसे सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत और अपराध को स्थापित करती है। अभियोजन शुरू करने के लिए निर्धारित उस समय अवधि तक, यदि कोई हो, समाप्त हो सकती है और उस स्थिति में ऐसी अवधि समाप्त होने के कारण संबंधित सरकारी कर्मचारी अभियोजन से बचने में सफल हो जाएगा, भले ही उसके द्वारा किए गए अपराध के पर्याप्त सबूत हों। हमारी राय में, ऐसी स्थिति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एक नियम बनाकर नहीं बनाई जा सकती है, जिसमें सेवा की शर्त के रूप में अभियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।"

(अपीलकर्ता द्वारा अवधारण दिया गया)

घ. ***कैलाश नाथ*** (पूर्व) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, ***कर्नाटक राज्य बनाम पी. गिरिधर कुडवा***[15] के मामले में उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

15. 2020 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 5723

"10. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए आरोप पत्र जारी करना, हालांकि देर से किया गया है, यह उचित है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हमारी यह भी राय है कि जब उक्त अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर 17.2.2006 के अपने जवाब में गलत जन्म तिथि दी है, तो वह बहुत पहले ही उनके द्वारा जारी की गई झूठी जन्मतिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति, यह एक उपयुक्त मामला है जहां आपराधिक मुकदमा शुरू करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में, हालांकि कर्नाटक सिविल सेवा नियमों के नियम 214 (3) और (6) में, शुरू में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए एक बाधा थी, पंजाब राज्य बनाम कैलाश नाथ, (1989) 1 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 321 : एआईआर 1989 सर्वोच्च न्यायालय 558 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के नियम को पढा है जो पंजाब सिविल सेवा में था और माना गया है कि यह आपराधिक मुकदमा चलाने के रास्ते में नहीं आएगा। इसलिए, वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए, हम न केवल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं, बल्कि याचिकाकर्ता-राज्य को कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए प्रतिवादी-अपराधी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रखते हैं, साथ ही तारीख के बाद सात साल तक सेवा में बने रहने के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी जन्मतिथि की जानबूझकर झूठी घोषणा करने के लिए भी सुरक्षित रखते हैं जिस पर उन्हें सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता थी और परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय नुकसान हुआ।

(अपीलकर्ता द्वारा अवधारण दिया गया)

9. रमेश की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने अभिनिश्चित हो कर कहा कि आक्षेपित आदेश अच्छी तरह से तर्कसंगत है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। *तर्क के पक्ष मे ,* उन्होंने प्रस्तुत किया:

अ. उच्च न्यायालय ने सही माना कि पुलिस प्रतिवेदन (आरोपपत्र) चार साल की परिसीमा अवधि के बाद दायर की गई थी, जैसा कि कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 के

नियम 214 के उप-नियम (6) (बी) के साथ पठित नियम 214 (3) के तहत प्रदान किया गया था।

आ. न्यायिक कार्यवाही को प्राथमिकी की तारीख से शुरू नहीं माना जा सकता है। कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 214 के उप-नियम (6) (बी) के अनुसार, न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की तारीख को वह तारीख माना जाता है जिस दिन मजिस्ट्रेट पुलिस प्रतिवेदन (आरोपपत्र) या शिकायत का संज्ञान लेता है। वर्तमान मामले में, आरोपपत्र कथित अपराध के सात साल बाद 2016 में ही दायर किया गया था और इसलिए, निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया था।

इ. आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण की धारा 197 (1) के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों सिविल सेवकों पर लागू होती है।

10. निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में न्यायोचित था, जैसा कि रमेश ने प्रार्थना की थी, (i) कथित घटना की तारीख के चार साल से अधिक समय बाद आरोप पत्र दायर किया गया था और (ii) अनुमोदन की कमी थी।

11. अपीलकर्ता द्वारा दी गई चुनौती की जांच नियम 214 को पहले पूरी तरह से पढ़कर करना उचित समझा जाता है। समझने में आसानी के लिए, नियम 214 का निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:

नियम 214

"**214 (1) (ए)** कदाचार या लापरवाही के लिए पेंशन रोकना या वापस लेना।

सरकार अपने पास पेंशन या उसके हिस्से को रोकने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है, चाहे वह स्थायी रूप से हो या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, यदि किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें एक विदेशी नियोक्ता के अधीन सेवा और सेवानिवृत्ति के बाद पुन:रोजगार पर प्रदान की गई सेवा शामिल है।

(ख) पेंशन से आथक हानि की वसूली:

सरकार अपने पास पेंशन से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखती है, सरकार या किसी विदेशी नियोक्ता को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान का पूरा या आंशिक हिस्सा जिसके तहत सरकारी कर्मचारी ने प्रतिनियुक्ति या अन्यथा काम किया है। यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी को उसकी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुन:रोजगार पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है:

बशर्ते कि कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा: बशर्ते कि जहां पेंशन का एक हिस्सा रोक दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है, पेंशन की राशि नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं की जाएगी।

(2) (क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पहले या उसके पुन:नियोजन के दौरान सेवा में रहते हुए स्थापित की जाती हैं, तो सरकारी कर्मचारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद, इस नियम के अधीन कार्यवाही मानी जाएगी और उस प्राधिकारी द्वारा जारी और संपन्न की जाएगी जिसके द्वारा वे उसी रीति से शुरू किए गए थे जैसे कि सरकारी कर्मचारी सेवा में जारी रहा हो:

परन्तु जहां विभागीय कार्यवाहियां सरकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संस्थापित की जाती हैं, वहां वह प्राधिकरण अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(आ) विभागीय कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवा में होने के दौरान शुरू नहीं की गई थी, चाहे वह उसकी सेवानिवृत्ति से पहले हो या उसके पुन:नियोजन के दौरान हो।

(१) सरकार की अनुमोदन के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा।

(२) ऐसी संस्था से चार वर्ष से अधिक समय पहले हुई किसी भी घटना के संबंध में नहीं होगा, और

(३) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित किया जाएगा जो सरकार निदेश दे और विभागीय कार्यवाहियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार जिसमें सरकारी कर्मचारी के संबंध में उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।

3. कोई न्यायिक कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहते हुए शुरू नहीं की गई है, चाहे वह उसकी सेवानिवृत्ति से पहले हो या उसके पुन:नियोजन के दौरान, किसी ऐसी कार्रवाई के कारण के संबंध में या ऐसी संस्था से चार वर्ष से अधिक समय पहले हुई घटना के संबंध में स्थापित नहीं की जाएगी।

4. एक सरकारी कर्मचारी के मामले में जो सेवानिवृत्ति की आयु या अन्यथा प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है या जहां उप-नियम (2) के तहत विभागीय कार्यवाही जारी रखी गई है, नियम 214 ए में प्रदान की गई अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

5. जहां सरकार ने पेंशन को रोकने या वापस लेने का फैसला नहीं किया है, लेकिन पेंशन से आर्थिक नुकसान की वसूली का आदेश दिया है, वहां वसूली आमतौर पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर से नहीं की जाएगी।

6. इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

अ. विभागीय कार्यवाहियों को उस तारीख को स्थापित माना जाएगा जिस दिन सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को प्रभारों का विवरण जारी किया गया है, या यदि सरकारी कर्मचारी को पहले की तारीख से निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसी तारीख को जब निलंबित किया गया हो;

आ. न्यायिक कार्यवाही को स्थापित माना जाएगा-

i. आपराधिक कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को किसी पुलिस अधिकारी की परिवाद या प्रतिवेदन , जिसका मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है; तथा

ii. दीवानी कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को अदालत में वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

12 नियम 214 कर्नाटक सिविल सेवा नियम, 1958 के भाग IV (शीर्षक के सामान्य नियम) के तहत अध्याय XV (शीर्षक के साधारण नियम) का हिस्सा है। एक सरल पढ़ने पर, नियम 214 पेंशन को रोकने और वापस लेने से संबंधित है। नियम 214 (1) (ए) एक ऐसा प्रावधान है जो सरकार को पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार देता है, ऐसे मामले में जहां पेंशनभोगी किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है। इस प्रावधान को पेंशनभोगी की सेवा की अवधि के दौरान किए गए कदाचार या लापरवाही के लिए लागू किया जा सकता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुन: रोजगार के दौरान प्रदान की गई कोई भी सेवा भी शामिल है।

13. नियम 214 (3) में किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई के कारण या घटना के घटित होने के चार साल बाद "न्यायिक कार्यवाही" शुरू करने पर रोक का प्रावधान है। जिस तारीख को न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई मानी जाती है, वह नियम 214(6)(b) के तहत प्रदान की गई है।

14. क्या नियम 214 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता या किसी समान कानून के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को दबाने के लिए कोई आवेदन है?

15. यह किसी विशेष प्रावधान के पाठ्य अर्थ को उसके प्रासंगिक महत्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए क़ानूनों की व्याख्या की एक स्वीकृत कला है; और, गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, दुभाषिया इसे संहिताबद्ध करने के लिए अंतर्निहित नीति को उजागर कर सकता है।

16. हमारी सुविचारित राय में, नियम 214 का मूलपाठ उस संदर्भ में पढ़ा जाता है जिसमें यह अप्रवर्तनीय है और इसकी अंतर्निहित नीति यह स्पष्ट करती है कि इसकी

प्रासंगिकता तभी उत्पन्न होगी जब सरकार, अपने विवेक से, पेंशनभोगी के कारण पेंशन को रोकने या वापस लेने के लिए इसे लागू करने का चुनाव करेगी। कदाचार के लिए या किसी भी नुकसान की वसूली के उद्देश्य से जो उसके अपराध के कारण हुआ है, निश्चित रूप से इस तरह के आह्वान के लिए पूर्व-शर्तों को पूरा करने के अधीन है। नियम 214, गठन के किसी भी नियम द्वारा, लंबित आपराधिक कार्यवाही को शुरू में ही खत्म करने या अपराध का संज्ञान लेने के बाद ऐसी कार्यवाही को दबाने के लिए कोई आवेदन नहीं है, इससे बेहतर कोई कारण नहीं है कि उसमें निहित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया है।

17. वजह साफ है। हालांकि नियम 214 एक अलग कार्यक्षेत्र में काम करता है, जो प्राथमिकी दर्ज करने और पुलिस प्रतिवेदन (आरोपपत्र) जमा करने और आपराधिक भ्रष्टाचार निवारण के अध्याय XII और XIV के तहत अपराध का संज्ञान लेने के बाद जांच और अभियोजन से अलग है, लेकिन दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है। नियम 214 के पीछे की नीति यह है कि एक पेंशनभोगी का पेंशन का अधिकार सेवा के दौरान और बाद में एक साफ-सुथरे अभिलेख पर निर्भर करता है। यह नियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि एक पेंशनभोगी सेवा के दौरान या सेवा छोड़ने के बाद भी कदाचार या आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने के बावजूद मुक्त न हो (क्योंकि भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन के लिए निरंतर पात्रता के लिए एक शर्त है)। इस प्रकार, एक स्वच्छ अभिलेख की आवश्यकता आवश्यक है। यह देखने की जरूरत नहीं है कि नियम 214 का दायरा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों से परे है, जो कानून के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए पेंशन को रोकने या वापस लेने में सक्षम बनाता है। नियम 214 में दी गई समय-सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी कि किसी भी पेंशनभोगी को सुदूर अतीत की घटनाओं के संबंध में अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए या उसकी पूरी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों को जारी करने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार न किया जाए। किसी विशेष मामले में, सरकार समय-सीमा के कारण पेंशन को रोकने या वापस लेने में असमर्थ हो सकती है, लेकिन इसे अपने आप में एक वैध जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जिसमें पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी शामिल है। दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में, या अपराध का संज्ञान लेने के

लिए, एक बार ऐसी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद। श्री कामत ने ठीक ही तर्क दिया है कि नियम 214 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के भाग XII या उसके अध्याय XIV के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जांच एजेंसियों को प्रदत्त शक्तियों को कम करने का प्रभाव पड़े। पेंशन को रोकने या वापस लेने के लिए किसी आदेश/कार्रवाई के बिना भी, भारतीय न्याय संहिताया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या किसी भी समान कानून के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध की जांच नियम 214 के तहत या किसी अन्य वैधानिक मंशा द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

18. वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, हम इस बात से चिंतित नहीं हैं कि क्या नियम 214 में शामिल समय-सीमा एक बार के रूप में काम करती है या नहीं, जो रमेश प्रासंगिक नियमों के अनुसार हकदार है, पेंशन को रोकने या वापस लेने के लिए नहीं, या क्या उस संबंध में कोई वैध आदेश/कार्रवाई हुई है। यहां, उच्च न्यायालय ने नियम 214 का हवाला देकर रमेश के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें निस्संदेह कोई आवेदन नहीं था। इस प्रकार, पहला आधार जिस पर कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है, वह स्पष्ट रूप से आरक्षणीय है।

19. इसके बाद, हम यह जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या उच्च न्यायालय ने रमेश के खिलाफ कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करना उचित था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं की गई थी।

20. भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अपराध करने के कृत्यों से स्पष्ट रूप से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 जिम्मेदार लोक सेवकों को संभावित कष्टप्रद आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करती है, जो कथित तौर पर लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय या कार्य करने का इरादा रखते हुए उनके द्वारा की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा सेवारत और सेवानिवृत्त लोक सेवकों दोनों तक फैली हुई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने से पहले, अनुमोदन प्राप्त की जानी चाहिए थी। स्वीकार किया जाता है कि कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं की

गई है और इसलिए हम मानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के अपराधों *के तहत* कार्यवाही को रद्द करना न्यायसंगत और उचित था।

22 हालांकि, उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की कार्यवाही को रद्द करने में गलती की क्योंकि उसने इस बात की सराहना नहीं की कि 26 जुलाई, 2018 से प्रभावी संशोधन से पहले धारा 19 केवल उन लोक सेवकों पर लागू होती थी जो अपराध का संज्ञान लेते समय पद पर थे। ***ए. श्रीनिवासुलु बनाम तमिलनाडु राज्य*** में निर्णय के अनुच्छेद 33 और 34 में[16], इस न्यायालय ने समझाया कि 2018 के अधिनियम 16 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किए जाने से पहले, धारा 19(1)(ए) के तहत पूर्व अनुमोदन केवल उन लोक सेवकों के लिए आवश्यक थी जो संज्ञान लेने के समय सेवा में थे, न कि उन लोगों के लिए जो सेवानिवृत्त हो गए थे। हालांकि, 2018 के संशोधन के बाद, उन लोगों के लिए भी पूर्व अनुमोदन आवश्यक हो गई जो अपराध किए जाने के समय सेवा में थे, भले ही वे संज्ञान लेने समय तक सेवानिवृत्त हो गए हों या नहीं। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि आरोपी संख्या 1 (उसमें) 1997 में सेवानिवृत्त हो गया था, आरोप पत्र 2002 में दायर किया गया था, और 2003 में संज्ञान लिया गया था। चूंकि संज्ञान लेने के समय आरोपी सेवा में नहीं था, इसलिए उसके अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।

23 इसलिए, चूंकि रमेश 31 मई 2012 को सेवानिवृत्त हो गया था और अपराध का संज्ञान केवल 3 जून 2016 को लिया गया था, इसलिए वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत संरक्षण का हकदार नहीं था। इस तरह की सुरक्षा उन्हें तभी उपलब्ध होती जब उनके सेवा में रहते हुए संज्ञान लिया जाता।

24 उपरोक्त कारणों से, अनुच्छेद 10 में तैयार किए गए मुद्दे का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पहले आधार पर कार्यवाही को पूरी तरह से और दूसरे आधार पर, आंशिक रूप से रद्द करने में भूल की।

25 इसलिए, अपीलें आंशिक रूप से सफल होती हैं। दंड नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी) और (डी) के तहत दंडनीय अपराध (अपराधों)

---

16. 2020 सर्वोच्च न्यायालय के मामले ऑनलाइन कर्नाटक 5723

के लिए कार्यवाही को रद्द करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया जाता है। रमेश के खिलाफ कार्यवाही बहाल की जाती है और ऐसे अपराधों के लिए जारी रह सकती है।

26 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 531 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया गया है; फिर भी, निरस्त कानून के तहत लंबित कार्यवाही को स्पष्ट रूप से जारी रखने की अनुमति है। इसलिए, हम देखते हैं कि रमेश पर भारतीय भ्रष्टाचार निवारण के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, लेकिन केवल निरस्त कानून के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जिसके लिए स्वतंत्रता सुरक्षित है।

27 उपरोक्त शर्तों पर अपीलों का निपटारा किया जाता है।

28 इससे जुड़े कोई आवेदन , यदि लंबित हैं, तो समाप्त किए जाते हैं।

29 जाने से पहले, हम औपचारिक रूप से दर्ज करते हैं कि यद्यपि वर्तमान अपीलीय कार्यवाही मुख्य रूप से दंडात्मक कानूनों और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से संबंधित रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुई थी, विशेष अनुमति याचिकाओं को सिविल याचिकाओं के रूप में पंजीकृत किया गया था। यदि कोई गलती हुई है, तो अभिलेख को सही करने के लिए, रजिस्ट्री विशेष अनुमति याचिकाओं को आपराधिक याचिकाओं के रूप में बदल सकती है और उसके आधार पर अपीलों को उचित संख्या प्रदान कर सकती है, जिसे आपराधिक पक्ष से उत्पन्न होने वाली अपील माना जाता है।

मामले का परिणाम: अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पणीया निधि जैन *के द्वारा तैयार की गई.:*

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।